साप्ताहिक
Live not just breaTHE

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

दि कार्मिक पोस्ट

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 9, अंक : 28 (प्रति बुधवार),इन्दौर, 28 फरवरी 2024 से 5 मार्च 2024 पेज :8 कीमत : 3 रुपये

पृथ्वी पर तिहरे संकटों से मुक़ाबले के लिए यूएन पर्यावरण सभा में जुटी दुनिया

ई दिल्ली। पर्यावरण पर विश्व संसद के रूप में देखे जाने वाली यूएन पर्यावरण सभा का छठा संस्करण (UNEA-6) केनया की राजधानी नैरोबी में सोमवार को आरम्भ हुआ है, जिसमें पृथ्वी पर मंडराते तिहरे संकटों जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता हानि व प्रदूषण से निपटने के लिए मज़बूत वैश्विक कार्रवाई पर चर्चा होगी. 182 देशों से सात हज़ार से अधिक प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए जुटे हैं, जोकि शुक्रवार तक चलेगी.

यह पर्यावरण सभा ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया जलवायु परिवर्तन के बढ़ते ख़तरे से जूझ रही है, 10 लाख से अधिक प्रजातियों पर विलुप्त होने का जोखिम मंडरा रहा है और असामयिक मौतों के लिए प्रदूषण एक बड़ी वजह बनता जा रहा है. यूएन पर्यावरण कार्यक्रम की कार्यकारी निदेशक इंगेर ऐंडरसन ने अपने वक्तव्य में कहा कि चिलचिलाती गर्मी, शक्तिशाली तूफ़ानों, लुप्त होती प्रकृति व प्रजातियों, क्षरण का शिकार होती मिट्टी, प्रदूषित हवा, प्लास्टिक प्रदूषण समेत अन्य चिन्ताजनक प्रभाव हम सभी महसूस कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि इनका सर्वाधिक असर, निर्धन व निर्बल समुदायों द्वारा महसूस किया जाता रहा है, जो इसके लिए ज़िम्मेदार भी नहीं हैं, मगर कोई भी इन प्रभावों से अछूता नहीं है.

ब्राज़ील में वर्ष 2012 में टिकाऊ विकास पर हुए यूएन सम्मेलन (Rio+20) के फलस्वरूप UNEA को स्थापित किया गया था, जो पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर उच्चतम निर्णय-निर्धारण निकाय है और यूएन के सभी 193 देश इसके सदस्य हैं.

वैश्विक प्राथमिकता

यूएन पर्यावरण सभा की बैठक हर दूसरे वर्ष आयोजित की जाती है, जिसमें वैश्विक पर्यावरणीय नीतियों और अन्तरराष्ट्रीय पर्यावरणीय क़ानूनों को विकसित करने पर चर्चा होती है.

इस सभा में लिए जाने वाले निर्णयों व प्रस्तावों के ज़रिये यूएन पर्यावरण कार्यक्रम के कामकाज को निर्धारित किया जाता है, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है.

UNEA-6 के दौरान प्रकृति-आधारित समाधानों, ज़हरीले कीटनाशकों, मरुस्थलीकरण, सौर विकिरण में बदलावों, सूखे के प्रति समुदायों व पारिस्थितिकी तंत्रों की सहनसक्षमता को मज़बूती प्रदान करने समेत अन्य विषयों पर चर्चा होगी.

महत्वाकाँक्षी कार्रवाई पर ज़ोर

यूएन पर्यावरण कार्यक्रम की शीर्ष अधिकारी इंगेर ऐंडरसन

ने बताया कि इस बैठक में नागरिक समाज, आदिवासी समुदाय, महिलाओं, व्यवसाय जगत समेत युवा पीढ़ी की आवाज़ों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है. इस सम्मेलन में सदस्य देशों द्वारा 19 प्रस्तावों पर विचार-विमर्श होगा, जोकि महत्वाकाँक्षी, बहुपक्षीय पर्यावरणीय कार्रवाई को मज़बूती प्रदान करने पर केन्द्रित हैं. इन प्रस्तावों में सौर विकिरण में ज़रूरी बदलावों, जलवायु न्याय, रसायन व अपशिष्ट प्रबन्धन समेत अन्य विषय शामिल हैं. यूएन कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि इन प्रस्तावों के ज़रिये नैट-शून्य उत्सर्जन की दिशा में बढ़ने, वायु व जल गुणवत्ता को बेहतर बनाने और सूखे के प्रति सहनसक्षमता निर्माण में मदद मिलेगी. उन्होंने प्रतिनिधियों से मज़बूत प्रस्तावों के मसौदे तैयार करने का आग्रह किया, ताकि वास्तव में ज़रूरी बदलाव सुनिश्चित किए जा सकें और तिहरे पर्यावरणीय संकटों से दुनिया को बचाया जा सके.

सरकार और जनता के बीच संवाद की कड़ी हैं पत्रकार - उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि पत्रकारिता चुनौतीपूर्ण कार्य है। पत्रकार कई कठिनाईयों का सामना करते हुए जनता की आवाज बुलंद करते हैं। पत्रकार सरकार और जनता के बीच संवाद की कड़ी हैं। सरकार और प्रशासन को कमियाँ बताकर पत्रकार उस कमी को दूर करने का माध्यम बनते हैं। लोकतंत्र को सशक्त करने का कार्य पत्रकारिता कर रही है। इसीलिए इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के ईको पार्क रीवा में आयोजित संभागीय सम्मेलन में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकार कल्याण के संबंध में जो मांगे रखी गई हैं उन पर भी समुचित कार्यवाही की जाएगी। समारोह में क्रिकेटर श्री सौम्य पाण्डेय, गायिका सुश्री मान्या पाण्डेय सहित श्रेष्ठ कार्य करने वाले विभिन्न जिलों के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। समारोह में संगठन के प्रांताध्यक्ष श्री शलभ भदौरिया, नगर निगम के अध्यक्ष श्री व्यंकटेश पाण्डेय, समाजसेवी गुरमीत सिंह मंगू तथा बड़ी संख्या में पत्रकारगण उपस्थित रहे।

नो सिंगल यूज प्लास्टिक अभियान, निगमकर्मियों ने बांटे जूट के थैले,पर्यावरण प्रदूषण के बढते खतरे को बताया

पलामू, मेदिनीनगर नगर निगम ने बुधवार की शाम पर्यावरण सुरक्षा अभियान चलाया, जिसमें नगरनिगम अंतर्गत सभी दुकानदारों और फुटपाथी बिक्रेताओं व अन्य सभी विक्रेताओं को प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी। साथ ही जूट से बने थैला एवं कागज का ठोंगा वितरित किया गया। बता दें कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे संबंधित निर्मित सभी सामग्रियों को पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टिकोण से प्रतिबंधित किया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर समय समय पर कार्रवाई भी की जाती रही है।

इस बीच नगर निगम के सिटी मैनेजर सतीश कुमार, प्रधान लिपिक धीरज कुमार, जमादार इश्तेयाक शाह एवं विष्णु राम सहित अन्य शामिल थे। सिटी मैनेजर ने बताया कि शहरी क्षेत्र में कचहरी चौक से जूट से बने थैला एवं कागज का ठोंगा वितरण कार्यक्रम की शुरूआत की गई। इसके बाद कोऑपरेटिव चौक, सट्टीक चौक, छहमुहान, सब्जी मंडी एवं अन्य जगहों पर किया गया। एक दुकानदार को पांच जूट के झोले एवं पांच ठोंगा दिया गया और नियमित इसी तरह के बैग में सामान खरीदने पर देने की सलाह दी गई, ताकि प्लास्टिक से पर्यावरण प्रदूषण के बढते खतरे को कम किया जा सके। करीब तीन घंटे तक अभियान चलाकर लोगों को नो सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जागरूक किया गया। सिटी मैनेजर ने कहा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर पर्यावरण (रक्षा) अधिनियम 1986 के तहत एक लाख तक जुर्माना एवं पांच वर्ष कारावास का सजा का प्रावधान है।

विकास व जनकल्याण के लिए जो कार्य तय कर लिए हैं उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती - उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

विकास की कड़ियाँ जुड़कर हो रहे नये प्रतिमान स्थापित - राज्य मंत्री श्री बागरी 158 करोड़ रुपए से रीवा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत शत-प्रतिशत आबादी को जलापूर्ति व्यवस्था के संवर्धन कार्य का भूमिपूजन

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि विकास व जनकल्याण के लिए जो कार्य तय कर लिए हैं उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में जनप्रतिनिधियों की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। कार्यक्रम में रीवा नगर निगम क्षेत्र की शत-प्रतिशत जनसंख्या को जलापूर्ति के उद्देश्य से अमृत 2.0 योजना के तहत 158 करोड़ रुपए के संवर्धन कार्य का भूमिपूजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरीय प्रशासन एवं आवास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी ने की।

रीवा नगर पालिक निगम क्षेत्र में वेटनरी कालेज के समीप नवीन जल शोधन संयंत्र परिसर में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि वर्ष 2003 के पूर्व तक रीवा की आबादी के आधे घरों में खारे पानी की सप्लाई होती थी। वर्ष 2003 के बाद रीवा शहर में अभियान चलाकर घर-घर तक मीठा पानी पहुंचाने का कार्य किया गया। शहर की वर्ष 2040 की संपूर्ण जनसंख्या को अनुमानित मानकर कार्ययोजना बनाते हुए 135 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से नल कनेक्शन द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए अमृत 2.0 योजना में 158 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना से फिल्टर प्लांट के अतिरिक्त 12 नई पानी की टंकियों का निर्माण होगा और 462 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूटरी पाइपलाइन का निर्माण कर 15 हजार नए घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नगरीय प्रशासन राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी ने कहा कि विकास की कड़ियाँ जुड़कर नए आयाम स्थापित कर रही हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल की दूरदृष्टि से रीवा व विन्ध्य में विकास हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में श्री शुक्ल अपनी महती भूमिका का निर्वहन भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीब, युवा, किसान व नारी शक्ति के विकास से ही देश अपने विकसित राष्ट्र का संकल्प पूरा कर पाएगा। उन्होंने कहा कि पानी हमारे लिए अमूल्य है। इसे व्यर्थ न बहने दें और इसकी एक-एक बूंद बचाएं तथा इसका संरक्षण व संवर्धन भी करें। उन्होंने विकसित भारत व विकसित विन्ध्य के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया। इस अवसर पर सांसद श्री जनार्दन मिश्र ने कहा कि रीवा शहर में आगामी वर्षों में जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए शुद्ध पानी पहुंचाने व अन्य सुविधाएं देने की श्री शुक्ल की दूरदृष्टि साधुवाद की पात्र है। उन्होंने कहा कि रीवा शहर में रोडमैप बनाकर सभी विकास के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनकल्याण की प्रतिबद्धता से सभी बाधाएं स्वयं ही दूर हो जाती हैं। कार्यक्रम में वरिष्ठ जन-प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी व नागरिक उपस्थित रहे।

पीएम मोदी ने दी सौगात, देश के सबसे लंबे केबिल ब्रिज का किया उद्घाटन

अहमदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को बड़ी सौगात दी है। ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ने वाले लगभग 2.32 किमी लंबे देश के सबसे लंबे केबल-आधारित पुल सुदर्शन सेतु का पीएम ने उद्घाटन किया। पहले इसे सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इस पुल का नाम बदलकर सुदर्शन सेतु या सुदर्शन ब्रिज कर दिया गया है।

अपने ड्रीम प्रोजेक्ट, ओखा-बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह गुजरात की विकास यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा।पीएम मोदी ने शनिवार को एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था, कल गुजरात के विकास पथ के लिए एक खास दिन है। उद्घाटन की जाने वाली कई परियोजनाओं में ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ने वाला सुदर्शन सेतु भी शामिल है। यह एक आश्चर्यजनक परियोजना है जो कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। बता दें कि बेट द्वारका ओखा बंदरगाह के पास एक द्वीप है, जो द्वारका शहर से लगभग 30 किमी दूर है, जहां भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल-आधारित पुल है, जो ओखा मुख्य भूमि और गुजरात में बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। 2.5 किलोमीटर लंबा यह पुल प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों दोनों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। केंद्र द्वारा 2017 में इस पुल का शिलान्यास किया गया था। इसका उद्देश्य ओखा और बेट द्वारका के बीच आने-जाने वाले भक्तों के लिए पहुंच को आसान बनाना है। इसके निर्माण से

पहले, तीर्थयात्रियों को बेट द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर तक पहुंचने के लिए नाव पर निर्भर रहना पड़ता था। 2.5 किमी लंबा यह पुल 978 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। गुजरात दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को जामनगर में जोरदार रोड शो के साथ अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे की शुरुआत की। मोदी, मोदी और भारत माता की जय के नारों के बीच जैसे ही पीएम मोदी का काफिला सर्किट हाउस की ओर बढ़ा, सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग खड़े हो गए।

कोल साइडिंग के लिए पर्यावरण संरक्षण मंडल की सहमति नहीं

जांजगीर- चांपा । नैला रेलवे स्टेशन के आगे फाटक के पास स्थित कोल साइडिंग में पर्यावरण नियमों की जमकर अनदेखी की जा रही है। रेलवे द्वारा इस साइडिंग के लिए जल एवं वायु संबंधी सहमति नहीं ली है। पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय ने इसके लिए सिनियर डिविजनल कामर्शियल मैनेजर बिलासपुर को कई बार नोटिस दी है मगर मंडल ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया है। वायु और जल प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन नहीं होने से यहां रोज प्रदूषण फैल रहा है। नगरवासियों को इससे परेशानी हो रही है मगर इस ओर किसी का ध्यान नहीं है।

नैला स्थित कोल साइडिंग में रोज बड़े पैमाने पर कोयला कोल वासरियों से पहुंचता है और यहां से मालगाड़ियों में लोड कर कोयला आगे भेजा जाता है मगर इस साइडिंग में जल, प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के नियमों के तहत जल एवं वायु से संबंधित सहमति नहीं ली गई है। इसके बाद भी कोल साइडिंग का संचालन बेधड़क जारी है। यहां पानी का छिड़काव नियमित नहीं किया जाता। कोयला लेकर पहुंचने वाले वाहन बिना तिरपाल ढंके यहां पहुंचते हैं मगर जल एवं वायु संबंधी सहमति के लिए आवेदन रेल वे ने पर्यावरण संरक्षण मंडल कार्यालय में अब तक नहीं किया है। इसके लिए पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय ने 19 जुलाई 2022 , 2 फरवरी 2023 और 26 जुलाई 2023 को नोटिस जारी कर जल एवं वायु संबंधी सहमति लिए जाने का निर्देश दिया है मगर अब तक इसके लिए सहमति लेना तो दूर विभाग ने आवेदन करना भी उचित नहीं समझा। रेलवे कोयला परिवहन कर करोड़ो रूपए परिवहन शुल्क प्राप्त कर रही है। कोलवासरी भी लाखों रूपए कमा रहे हैं मगर नगरवासियों के हिस्से में केवल कोयले का प्रदूषण ही आ रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय छग पर्यावरण संरक्षण द्वारा नोटिस में कहा गया है कि नियमानुसार जल एवं वायु के लिए सहमति प्राप्त नहीं करने पर पर्यावरणीय क्षति पूर्ति के लिए जुर्माना लगाएगी और वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी मगर मंडल के इस नोटिस को लेकर रेलवे गंभीर नहीं है। कोल साइडिंग में बेतरतीब ढंग से कोयला परिवहन किया जाता है। जिसके चलते साइडिंग से आगे अंडर ब्रिज का उपयोग आवागमन करने वाले लोग नहीं कर पाते और उन्हें फाटक खुलने का इंतजार करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति बाइक या साइकिल से अंडरब्रिज की ओर जाता है तो कोयले की धूल से उसके कपड़े काले हो जाते हैं। ऐसे में फाटक के सामने खड़े होकर उसके खुलने का इंतजार करना लोगों की मजबूरी है। कोल साइडिंग के पास ही लोगों का खेत है और एक नाला भी पास में ही है। साइडिंग से कोयले की धूल और वर्षा होने पर कोयला युक्त पानी लोगों के खेतों के अलावा नाले में भी मिलता है। यह नाला कंजी नाले में जाकर मिलता है और उसका पानी भी प्रदूषित होता है।

11 लाख का पैकेज छोड़ आशुतोष पांडे पैदल निकल पड़े पर्यावरण बचाने की 16 हजार किमी लंबी पैदल यात्रा पर

विदिशा। पर्यावरण को लेकर आज भी हम जागरूक नहीं हो पाए और धर्मनगरी अयोध्या का एक युवा आशुतोष पांडे अपनी 11 लाख रुपए सालाना वेतन वाली नौकरी छोड़कर सिर्फ पर्यावरण की अलख जगाने 16 हजार किमी की पदयात्रा पर निकल पड़ा है। इस पदयात्रा को उन्होंने वंदे भारत नाम दिया है।

युवा करीब 11 हजार किमी की पदयात्रा कर विदिशा पहुंचा और कलेक्टर उमाशंकर भार्गव से मुलाकात कर अपने मिशन की जानकारी दी। आज वह शहर में पौधारोपण कर अपने अभियान में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री का साथ पाने के लिए छतरपुर रवाना होगा। कहने को तो उनकी उम्र महज 25 वर्ष है, परंतु हौसला और हिम्मत पहाड़ जैसी। आशुतोष। 22 दिसबंर 2022 को पर्यावरण संरक्षण के लिए पैदल ही भारत यात्रा पर निकल पड़े। उत्तर प्रदेश से चलकर वे बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत 13 राज्यों से होते हुए विदिशा पहुंचे हैं। अब तक आशुतोष 21 राज्य, 75 जिले, 1700 गांवों से लोगों को जागरूक करते हुए जा रहे हैं। आशुतोष के मन में प्रकृति संरक्षण का संदेश देने का यह विचार कहां से आया? यह पूछने पर वे कहते हैं- कोरोना काल में आक्सीजन की पूर्ति न होने से मेरे एक प्रिय मित्र की मृत्यु हो गई थी। उस क्षण लगा कि यदि आक्सीजन नहीं, प्रकृति नहीं, पर्यावरण नहीं है तो फिर हम सबका जीवन क्षणभंगुर है। यही विचार मन को मथता रहा और एक दिन ऐसा भी आया जब करीब 11 लाख रुपये सालाना की नौकरी छोड़कर पर्यावरण बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रण लिया और पैदल भारत यात्रा शुरू कर दी।

आशुतोष %सेव द इन्वायरमेंट% लिखा बोर्ड लेकर अपने बैग में तिरंगा लगाए लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक कर रहे हैं। बोर्ड में पैदल 16,000 किमी चलने का लक्ष्य भी लिखा है। आशुतोष प्रतिदिन करीब 30 किमी चलते हैं। मध्य प्रदेश के बाद वे राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए अयोध्या पहुंचेंगे। आशुतोष ने बताया कि जब नौकरी छोड़कर पैदल भारत यात्रा की ठानी, तो परिवार के लोग सन्न रह गए। पहले सबने विरोध किया और चिंता जताई। कुछ रिश्तेदार तो मुझे मानसिक रूप से विचलित बताकर डाक्टर को दिखाने तक की बातें करने लगे थे। किंतु मैं अपने संकल्प से डिगा नहीं। परिवार ने जब मेरा जुनून देखा तो मेरा यह संकल्प पूरा करने में साथ दिया। आशुतोष ने बताया कि आए दिन आए शोध बताते हैं कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली में रहने वालों की उम्र कम होती जा रही है। फिर भी हम नहीं सुधर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं हो रहे हैं। इसके लिए हम सब भारतवासियों, खासकर युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। अगर कुछ वर्षों तक हमने और लापरवाही की, तो जलवायु परिवर्तन से मनुष्यों का ही नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी का बहुत नुकसान होगा। यह अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं वाली स्थिति है। आशुतोष ने पैदल भारत यात्रा का अंतिम पड़ाव श्रीराम की नगरी अयोध्या को रखा है। वे दो वर्ष बाद अर्थात जनवरी 2026 में अयोध्या पहुंचने का लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं। तब अयोध्या में एक लाख पौधों का रोपण किया जाएगा, जिसे श्रीराम वाटिका नाम दिया जाएगा। आशुतोष बाद में अपनी टीम के साथ उस वाटिका का संरक्षण भी करेंगे।

डब्ल्यूटीओ बैठक- सब्सिडी के मामले में मछुआरों के हितों से नहीं किया जाएगा समझौता, भारत ने किया साफ

नई दिल्ली। भारत ने डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में स्पष्ट कर दिया है कि वो मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। गौरतलब है कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दूसरे दिन मत्स्य पालन को दी जा रही सब्सिडी पर एक वार्ता सत्र का आयोजन किया गया था। वार्ता में, भारत ने अपनी दृढ़ धारणा को एक बार फिर से दोहराया है कि मत्स्य पालन के साथ पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और इसके प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। भारत का कहना है कि यह धारणा देश में मछुआरों के विविध समुदायों की परंपराओं और लोकाचार में गहराई से निहित है।

ऐसे में मछली पकड़ने की सब्सिडी पर किसी भी व्यापक समझौते में उन मछली पकड़ने वाले समुदायों के हितों और कल्याण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो अपनी जीविका के लिए समुद्री संसाधनों पर निर्भर हैं। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय मछुआरे मछली पकड़ने के दौरान पहले ही पर्यावरण का ख्याल रखते हैं और इस नाम पर उनकी रोजी-रोटी पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। भारत का कहना है कि भारतीय मछुआरों की तुलंना विकसित देशो में मछली का कारोबार करने वाली कॉरपोरेट कंपनियों से नहीं की जानी चाहिए। भारत में मछुआरे अपनी जीविका और भरणपोषण के लिए मछली पकड़ने का काम करते हैं। ऐसे में यदि मत्स्य पालन पर सब्सिडी को लेकर कोई भी नियम बनता है तो उसके लिए एक व्यापक नीति बनाई जानी चाहिए। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अतीत में मत्स्य पालन क्षेत्र को दी गई सब्सिडी के चलते समुद्री संसाधनों का बहुत ज्यादा शोषण हुआ है। लेकिन साथ ही यह नहीं भूलना चाहिए कि विकासशील देशों और छोटी अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह सब्सिडी बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि वे अपने मत्स्य उद्योग को बेहतर बना सकें और अपने मछुआरों की खाद्य सुरक्षा और जीविका की रक्षा कर सकें। यह वार्ता स्थिरता की अवधारणा से जुड़ी है ऐसे में मत्स्य पालन को दी जाने वाली सब्सिडी पर किसी भी व्यापक समझौते में इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि अलग-अलग देशों की अपनी अलग-अलग जिम्मेवारियां और क्षमताएं हैं। ऐसे में इसे सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों एवं संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांतों का पालन करते हुए तैयार किया जाना चाहिए। इसमें विशेष और विभेदक उपचार (एस एंड डीटी) के प्रावधानों को भी उचित रूप से शामिल किया जाना चाहिए, जैसा कि सभी डब्ल्यूटीओ समझौतों के लिए होता है। बता दें कि विश्व व्यापार संगठन के समझौतों में ऐसे प्रावधान शामिल हैं, जो विकासशील देशों को डब्ल्यूटीओ ढांचे के तहत विशेष अधिकार देते हैं। इन अधिकारों को विशेष और विभेदक उपचार प्रावधान कहा जाता है।

पर्यावरण के लिहाज से सही नहीं बड़े पैमाने पर होता दोहन- इसके साथ ही स्थिरता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और इस तरह के समझौते को प्रभावी और सशक्त बनाने के लिए ऐसी सब्सिडी देना बंद करना होगा, जो विशेष रूप से मछली पकड़ने के ईंधन के लिए नहीं है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सरकारों के बीच सौदों के माध्यम से मछली पकड़ने के अधिकार बड़ी कंपनियों को हस्तांतरित न हों। साथ ही मछली पकड़ने के क्षेत्रों से दूर मौजूद देशों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को नियंत्रित करना भी बेहद महत्वपूर्ण है, जैसा कि दस्तावेज आरडी/टीएन/आरएल/175 में भारत द्वारा सुझाया गया है।

भारत ने सभी सदस्य देशों से अपने जल क्षेत्र (ईईजेड) से परे मछली पकड़ने या सम्बंधित गतिविधियां चलाने वाले देशों से कम से कम 25 वर्षों तक सब्सिडी पर रोक लगाने के आग्रह किया है। बता दें कि समुद्र तट से 200 समुद्री मील से अधिक दूरी पर मछली पकड़ने को सुदूर क्षेत्र कहा जाता है।

भारत ने सदस्य देशों को यह भी यदि दिलाया है कि बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने को दी जा रही सब्सिडी, पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। इतना ही नहीं इसकी वजह से समुद्री संसाधनों के उचित प्रबंधन पर भी असर पड़ता है।

ऐसे में भारत ने सदस्य देशों से कहा है कि उन्हें बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन पर सब्सिडी के नुकसानदायक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि साथ ही भारत का यह भी कहना है कि विकासशील देशों और कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपने मत्स्य क्षेत्र को विकसित करने और विविधता लाने के साथ-साथ मछुआरों की खाद्य सुरक्षा और जीविका की रक्षा के लिए सब्सिडी बेहद जरूरी है।

भारत का आगे कहना है कि बहुत ज्यादा और क्षमता से अधिक मछली पकड़ने (ओसीओएफ) को सम्बोधित करने के मौजूदा दृष्टिकोण में गहरी खामियां हैं। भारत के मुताबिक चूंकि सदस्य देश जरूरत से ज्यादा पकड़ी जा रही मछलियों के मुद्दे से निपटने के लिए एक सकारात्मक दृढ़ संकल्प दृष्टिकोण का उपयोग करने पर सहमत हुए हैं, ऐसे में सदस्यों को इस पद्धति का उपयोग करना चाहिए।

इसके साथ ही भारत ने इस बात पर भी गौर करने को कहा है कि हर साल इस सब्सिडी के रूप में कितना पैदा दिया जा रहा है, जिसकी पूरी तस्वीर सामने नहीं आती है। हमें इस बात पर भी विचार करने की जरूरत है कि प्रत्येक मछुआरे को कितनी सब्सिडी मिल रही है। साथ ही, किस देश का मछली पकड़ने का क्षेत्र (ईईजेड) कितना बड़ा है, उसकी तटरेखा कितनी लम्बी है और छोटे मछुआरों की आबादी कितनी है। भारत ने दोहराया है कि सदस्य देशों द्वारा यूएनसीएलओएस के तहत उनके स्वयं के जल क्षेत्र (ईईजेड) में मत्स्य पालन के स्थाई प्रबंधन के लिए एक-दूसरे के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। बता दें कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का यह 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 26 फरवरी 2024 से अबू धाबी में शुरू हो चुका है। इस सम्मेलन के दौरान भारत ने कृषि पर हुई वार्ता में पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग (पीएसएच) के स्थाई समाधान को अंतिम रूप देने की वकालत की थी। गौरतलब है कि यह मामला पिछले 11 वर्षों से अटका है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008